Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 2 | Issue 3 | (July – Sep 2025)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका - चौदहवीं विधानसभा से सत्रहवीं विधानसभा के विशेष संदर्भ में

डॉ. आभा बाजपेयी [1], कपिल शर्मा [2]
[1] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका चौदहवीं विधानसभा से सत्रहवीं विधानसभा के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा और विधानसभा में सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य भयंकर प्रतिस्पर्धा, वैचारिक टकराव और बदलती मतदाता निष्ठाओं से चिह्नित है। ऐसे गतिशील माहौल में, विपक्ष की भूमिका न केवल सत्तारूढ़ सरकार पर अंकुश लगाने के रूप में, बल्कि वैकल्पिक आवाजों और नीतियों के प्रतिनिधि के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 14वीं से 17वीं विधानसभा (2002-2022) तक का समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए परिवर्तनकारी था। इस युग में प्रारंभ में गठबंधन की राजनीति का उदय, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन और भारतीय जनता पार्टी का पुनरुत्थान देखा गया। इन वर्षों के दौरान विपक्ष ने सत्तारूढ़ दलों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाईं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता में काफी भिन्नता थी। इस शोध पत्र का उद्देश्य इस अवधि के दौरान विपक्षी दलों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण करना, उनकी सफलताओं और विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। चुनावी नतीजों, विधायी प्रदर्शन और सार्वजनिक स्वागत की जांच करके, अध्ययन विपक्षी दलों के सामने आने वाली चुनौतियों और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है।

मुख्य शब्द :- उत्तर प्रदेश विधान सभा, सत्ता पक्ष, सशक्त विपक्ष, चुनाव, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल

प्रस्तावना :-

उत्तर प्रदेश विधानसभा राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण एवं विस्तृत विधानसभा है। यहां भारत के समस्त प्रदेशों में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें हैं अतः यह केंद्र की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का भी वर्चस्व रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत से, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के उदय में बदलाव देखा गया है। इस अवधि में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी देखी गई, जो बड़े पैमाने पर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रेरित थी। 1991 के चुनावों में, जहां भाजपा का दबदबा था, राज्य में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभुत्व ख़त्म हो गया। जाति-आधारित राजनीति के उद्भव, विशेष रूप से दलित सशक्तीकरण पर बसपा के फोकस और सपा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को एकजुट करने के कारण, ने एक नया राजनीतिक ढांचा तैयार किया। सामाजिक गठबंधनों के इस पुनर्गठन ने खंडित चुनावी परिणामों, गठबंधन सरकारों और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया। 2002 से 2022 के बीच विधानसभा कार्यकाल का विश्लेषण इस परिवर्तन को दर्शाता है। प्रत्येक कार्यकाल ने विपक्षी दलों के लिए अद्वितीय चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत किए, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में उनके रणनीतिक अनुकूलन को उजागर करते हैं। चौदहवीं विधानसभा से सोलहवीं विधानसभा तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमुख पार्टियां रहीं। इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों ने प्रदेश की सत्ता में तथा विपक्ष में बारी –

बारी से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया तथा सत्रहवीं विधानसभा के चुनावों ने प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रदेश की राजनीति में विपक्ष में भी अपना स्थान नहीं बना पार्टी थी उस दल का प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सत्रहवीं विधानसभा के चुनाव 2017 में 303 सीटें प्राप्त कर सरकार बनाई और समाजवादी पार्टी को 47 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण दृढ़ता के साथ विधानसभा में एक सशक्त विपक्ष के रूप में भूमिका का निर्वहन किया।

विपक्ष की रणनीतियाँ और प्रदर्शन :-

14वी विधानसभा : 2002- 2007

2002 के विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश आया और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने 160 सीट और बहुजन समाज पार्टी ने 106 सीट प्राप्त कर प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुल 91 सीट प्राप्त की और भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 27 सीट प्राप्त हुई। इस अवधि में गठबंधन सरकारें देखी गईं। शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। चौदहवीं विधानसभा के प्रथम चरण में सुश्री बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। इस समय विपक्ष की भूमिका कम थी, क्योंकि आंतरिक मतभेदों और बदलते गठबंधनों ने लगातार रणनीतियों में बाधा उत्पन्न की। परंतु इस दौर में नेता विरोधी दल मोहम्मद आजम खां, समाजवादी पार्टी (13.05.2002-29.08.2003) ने विधानसभा में विद्युत समस्याओं, किसानों की समस्याओं उच्च शिक्षा के विकास इत्यादि पर प्रश्न उठाए। और विपक्षी दलों द्वारा प्रमुख रणनीतियों अपनाई गई जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन को कमजोर करने के लिए बिजली की कमी और कृषि संकट जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाया गया। विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार के घोटालों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया। विपक्ष ने सरकार में भाजपा की भूमिका की आलोचना के रूप में सांप्रदायिक तनाव को उजागर किया। जबकि कार्यकाल के अंत में सपा ने गति पकड़ी, विपक्ष की एकजुट मोर्चा पेश करने में विफलता ने इसकी समग्र प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सत्ता में काबिज बहुजन समाज पार्टी में फूट डाली और स्वयं सत्ता में आकर सरकार की कमान संभाली। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केवल 1 वर्ष 3 माह 26 दिन सरकार चली। तत्पश्चात सत्ता में काबिज बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया और समाजवादी पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई । इस दौरान विपक्ष में ने सत्ता पक्ष पर परिवारवाद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इत्यादि मुद्दों को विधानसभा से लेकर जमीनी स्तर पर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसमें सबसे प्रमुख हथियार विपक्ष का गुंडागर्दी, अराजकता का मुद्दा था इसे मुद्दे को लेकर नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी (30.08.2003-07.09.2003) और श्री लाल जी टंडन भारतीय जनता पार्टी (07.09.2003-13.05.2007) ने विधानसभा में कई बार सत्ता पक्ष को घेरा और विधानसभा के बाहर भी गुंडागर्दी, अराजकता, जमीन पर कब्जा, भ्रष्टाचार को लेकर जमीनी स्तर पर जनता के सामने रखा। विपक्षी दलों ने इस कार्यकाल में महिला सुरक्षा, विधवा पेंशन, एक जाति वर्ग को विशेष लाभ, बेरोजगारी मुद्दों पर सरकार को घेरा।

15वी विधानसभा : 2007-2012

15 वीं विधानसभा 2007 के चुनावों में सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण जीत हुई। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक सीट (226 विधानसभा सीट) प्राप्त हुईं और समाजवादी पार्टी ने 100 सीट के साथ प्रमुख विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। बहुजन समाज पार्टी 'सर्वजन

हिताय सर्वजन सुखाए' नारे में समाहित दलित-ब्राह्मण एकता पर उनका ध्यान मतदाताओं को पसंद आया। बहुजन समाज पार्टी ने विशेष रूप से बाह्मण मतदाताओं को खुद से जोड़ने के लिए दलित बाह्मण भाईचारा सम्मेलन आयोजित करने के साथ नारा दिया पंडित शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। विपक्ष, विशेषकर सपा और भाजपा ने इस कथा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए संघर्ष किया। इस अवधि के दौरान, नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी (14.05.2007 – 26.05.2009) ने सुश्री मायावती की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के प्रतीक के रूप में निशाना बनाया और विधानसभा तथा जमीनी स्तर तक प्रस्तुत किया तत्पश्चात नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी (26.05.2009- 09.03.2012) ने भूमि अधिग्रहण नीतियों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सत्ता में काबिज बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका कार्यकाल कभी अच्छा नहीं रहा। इसलिए इस बार भी कोई चमत्कार होने की संभावना नजर नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो न केवल अनुभवहीन हैं, अकुशल और भ्रष्टाचारी भी हैं। यह मंत्रिमंडल पूरी तरह प्रदेश की जनता के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार ने किसानों के हितों के साथ-साथ उद्योग धंधों को भी बर्बाद कर दिया है। बजट केवल 0.5 प्रतिशत आबादी के लिए तैयार किया गया है। किसानों के लिए पोषित गेहूं का सरकारी खरीद मूल्य किसानों को गरीबी की ओर ढकेलेगा उन्हें उनकी लागत मूल्य भी ये सरकार नहीं देना चाहती। प्रदेश में आलू मिट्टी के मोल बिक रहा है। सारे प्रदेश में विद्युत संकट ने चुनाव के बाद से अंधेरा कर दिया है अधिकारियों की मनमानी के कारण विद्युत परिषद और परिवहन विभाग में घाटा ही घाटा हो रहा है। परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर उद्घाटन के जो पत्थर बनाए जा रहे हैं उनसे सरकार के प्रति ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपराध, हत्या, बलात्कार, डकैती तथा माफिया का आतंक उत्तर प्रदेश में सामान्य बात हो गई है जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। अपराध में लिप्त अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है और उद्योगपति पलायन कर रहे हैं प्रदेश आर्थिक रूप से 50 वर्ष पीछे चला गया है अगर यही स्थिति रही तो प्रदेश का विकास कभी संभव नहीं है। नेता विरोधी दल ने सरकार के अंतिम वर्ष में सरकार द्वारा निर्माण किए जा रहे पार्कों, स्मारकों, हाथियों के निर्माण भूमि अधिग्रहण इत्यादि मुद्दों को विधानसभा में रखा और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य विरोधी दलों ने सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सम्मुख रखा। प्रदेश में जहां कहीं भी किसी भी जगह कोई अत्याचार होता या किसी को उत्पीड़ित किया जाता मुलायम सिंह यादव मौके पर पहुंचकर स्थिति का गहराई के साथ अध्ययन करते और फिर पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को शासन के समक्ष रखते थे। वह नेता विरोधी दल होने के नाते मात्र सरकार की आलोचना करने में ही विश्वास नहीं रखते बल्कि शासन द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना भी करते थे। विधानसभा में एक बार नेता विरोधी दल की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि लोकतंत्रात्मक शासन में व्यवस्था में विरोधी दलों का महत्व जितना अधिक है उनकी भूमिका भी उतना अधिक उपयोगी है।

16वी विधानसभा : 20012-2017

16वी विधानसभा , 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी 403 सीटों में से 228 सीटें प्राप्त कर बहुमत के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में उभरी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सत्ता में वापसी ने राज्य की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव को चिह्नित किया और बहुजन समाज पार्टी को 79 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 29 सीट, राष्ट्रीय लोक दल को 08 सीट एवं अन्य निर्दलीयों को प्राप्त हुई। इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (16.03.2012-26.06.2016) एवं गया चरण दिनकर (27.06.2016-17.03.2017) ने नेता विरोधी दल की भूमिका का निर्वहन किया।

विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने कई बार राज्य की बिगड़ती कानून- व्यवस्था की स्थिति को उठाया और दलितों के खिलाफ जाति – आधारित भेदभाव और हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा किया। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर जोर दिया और समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों की सुरक्षा से समझौता किया। विपक्ष ने विशेषकर भाजपा ने खराब बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त रोजगार सृजन और धीमी औद्योगिक वृद्धि को महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में उजागर किया। सामाजिक न्याय और कल्याण मुद्दे समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कल्याण योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना विवाद का एक और मुद्दा था। विपक्ष ने दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों का हवाला देते हुए कन्या विद्या धन योजना और किसानों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रमों जैसी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावकारिता पर सवाल उठाया। विकास और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित अखिलेश के अभियान ने विविध मतदाता आधार को आकर्षित किया। हालाँकि, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार को चुनौती देने के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ अपनाईं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक अराजकता, सांप्रदायिक तनाव (मुजफ्फरनगर दंगे) और सत्ता विरोधी लहर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विपक्ष ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल अपराधों का लगभग 11.6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में था, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। विशेषकर राज्य में 2013 में सांप्रदायिक दंगों की 6798 घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्षों की तुलना में भारी वृद्धि है। विपक्ष ने सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के उदय ने भी पार्टी का कायाकल्प कर दिया। बसपा की रणनीति विशेष रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और दलित मुद्दों को संबोधित करने में सपा की शासन विफलताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस की भूमिका राज्यव्यापी रणनीति के बजाय विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक छोटी भूमिका निभाई। जबकि विपक्ष ने शासन की खामियों को प्रभावी ढंग से उजागर किया, इस अवधि के दौरान भाजपा द्वारा तैयार किया गया आधार 2017 में उसकी व्यापक जीत में सहायक बन गया।

17वी विधानसभा: 2017-22

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्रहवीं विधानसभा 2017 का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, इस चुनाव में काफी वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बारी से बारी से बन रही सरकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में 303 सीट प्राप्त कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीट प्राप्त हुई जबकि बहुजन समाज पार्टी को मात्र 14 सीटों से संतोष करना पड़ा। सत्रहवीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने श्री रामगोविन्द चौधरी को नेता विरोधी दल बनाया।

भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा ने विजय का आगाह वर्ष 2014 में सोलहवीं लोकसभा चुना में हो गया था। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी तरह वर्ष 2017 सत्रहवीं विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा और चुनाव के समय कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं रखा। यह चुनाव सपा बसपा से निजात पाने, भ्रष्टाचार रोकने, कानून व्यवस्था बहाल करने विशेषकर हिंदुत्व एवं राम मन्दिर के नाम लड़ा गया। हिन्दुत्वविजय के पश्चात् विपक्ष, विशेष रूप से सपा और बसपा, ने भाजपा के हिंदुत्व आख्यान और विकास और कल्याण योजनाओं पर उसके फोकस का मुकाबला करने के लिए संघर्ष किया। विपक्ष, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में छोटे दलों के साथ विधायी परिणामों को आकार देने और सरकार को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यों की कठोर विधायी निगरानी और जांच प्रदान करके अपने जनादेश का प्रयोग करते हैं। वे कानून व्यवस्था से लेकर सामाजिक आर्थिक नीतियों तक के मुद्दों पर मंत्रियों और अधिकारियों से

पूछताछ करने के लिए प्रश्नकाल, बहस और समिति की कार्यवाही जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। इस विधानसभा में विपक्ष संख्यात्मक रूप से कम होने के बाबजूद भी यह कार्यकारी निर्णयों की जांच, संशोधन का प्रस्ताव और समावेशी नीतियों की वकालत करके सत्तारूढ़ डालबके भीतर अनियंत्रित शक्ति की एकाग्रता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा एक नई सोशल इंजीनियरिंग सपा बसपा गठबंधन द्वारा की गई, ओबीसी और दलित वोटों को एकजुट करने का प्रयास किया गया लेकिन यह गठबंधन गति बनाए रखने में विफल रहा। कांग्रेस की रणनीति "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन का अभाव था। विरोध और आंदोलन विपक्षी दलों ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच कुछ आकर्षण पैदा हुआ। इन प्रयासों बावजूद, राष्ट्रवाद और कल्याण की राजनीति के इर्द-गिर्द हावी होने की भाजपा की क्षमता ने विपक्ष के अभियानों पर ग्रहण लगा दिया।

सफलता एवं असफलता का तुलनात्मक विश्लेषण :-

विपक्ष की सफलता में योगदान देने वाले कारक जाति और क्षेत्रीय पहचान की प्रभावी लामबंदी है। शासन की विफलताओं, जैसे कानून और व्यवस्था के मुद्दे, को संबोधित करना। विपक्षी दलों के बीच सहयोग, जैसे 2019 में गठबंधन (हालांकि प्रभाव में सीमित)।

विपक्ष की विफलता के लिए अग्रणी कारक विपक्षी दलों में एकजुट नेतृत्व और दूरदर्शिता का अभाव। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर भाजपा के आख्यान का मुकाबला करने में असमर्थता। कमजोर जमीनी स्तर का संगठन और मतदाताओं से कटाव। व्यापक विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित किए बिना जाति-आधारित राजनीति पर अत्यधिक निर्भरता।

1. उत्तर प्रदेश में विपक्ष तब सबसे प्रभावी रहा जब उसने शासन की विफलताओं को उजागर किया और स्थानीय मुद्दों को उठाया।
2. 2017 के बाद से भाजपा का प्रभुत्व जाति और समुदाय के आधार पर मतदाता आधार को मजबूत करने की क्षमता को दर्शाता है, जो राष्ट्रवाद और विकास की एकीकृत कथा प्रस्तुत करता है।
3. भाजपा के उदय के मद्देनजर सपा और बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को अस्तित्व संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करने की जरूरत है।

निष्कर्ष :-

उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विपक्ष को एक सक्रिय समावेशी और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न केवल आलोचना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक समाधान पेश करने गठबंधन बनाने और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ाना बढ़ावा देना चाहिए एकता पारदर्शिता और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से विपक्ष सत्तारूढ़ दल को चुनौती देना जारी रख सकता है। अधिक जवाब देही सुनिश्चित कर सकता है और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की भलाई के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वकालत कर सकता है यह न केवल राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक है बल्कि यह सुरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है कि सार्वजनिक नीति के निर्माण में समाज के सभी वर्गों की जरूरत को संबोधित किया जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रत्येक विधानसभा में विपक्ष में सभी

राजनीतिक दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो सभी ने एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाया है। अतः लोकतंत्र में विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -:

1. दुबे, प्रदीप कुमार. (2020). उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपदेशों और उनमें माननीय सदस्यों की उपस्थिति द्वितीय भाग. लखनऊ, विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश विधान भवन.
2. दुबे, प्रदीप कुमार. (2017). उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दलों का उद्भव एवं विकास. लखनऊ, विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश विधान भवन.
3. दुबे, प्रदीप कुमार. (2017). उत्तर प्रदेश विधान सभा के महत्वपूर्ण विधायन. लखनऊ, विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश विधान भवन.
4. दुबे, प्रदीप कुमार. (2017) उत्तर प्रदेश में संविद सरकारें. लखनऊ, विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश विधान भवन.
5. सिंह, एस.पी. (2007). मायावती और बहुजन समाज पार्टीर उत्तर प्रदेश में जाति और सत्ता की राजनीति.
6. राय, पी. (2017). उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीतिर मतदाता व्यवहार का एक अध्ययन.
7. वर्मा, ए.के. (2014). उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका (1991-2012).
8. कुमार, एस. (2019). एसपी-बीएसपी गठबंधन और इसके निहितार्थ राजनीतिक रणनीतियों का एक विश्लेषण.
9. गुप्ता, ए. (2012). एक राजनीतिक रणनीति के रूप में कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति.
10. कश्यप, डॉ सुभाष (1972). भारत के राजनीतिक दल: नीतियां और कार्यक्रम. नई दिल्ली, सांविधानिक तथा संसदीय संस्थान.